



विपक्ष की गलत सूचना के बावजूद कर्नाटक की अर्थव्यवस्था मजबूत: सीएम @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | रविवार, 23 फरवरी, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : <https://www.shubhlabhdaily.com> | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | * मूल्य-6 रु. | वर्ष-7 | अंक-53

पीएम मोदी ने भारत के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं

2047 तक विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी : अमित शाह

पुणे, 22 फरवरी (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में वेस्टर्न रीजनल काउंसिल (पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोऑपरेटिव सेक्टर के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने भारत के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं- 2047 तक विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। इन दो लक्ष्यों को कोऑपरेटिव सेक्टर के योगदान से हासिल किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने अलग केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के काम और उसके प्रभाव की सराहना करते हुए कहा, इस मंत्रालय के माध्यम से देश में बहुत सी चीजों में क्रांति आई है। मंत्रालय सहकार से समृद्धि के आदर्श वाक्य पर काम करता है। और यह जनता सहकारी बैंक भी उसी तर्ज पर काम करता है। अमित शाह ने देश के कोऑपरेटिव सेक्टर से टेक्नोलॉजी को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, दोस्तों, आज जब हम सहकारी समितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि हमें प्रौद्योगिकी को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में महाराष्ट्र के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा, अगर हम देश में सहकारी और



जनता सहकारी बैंक है, छोटे लोगों का बड़ा बैंक...

शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक नजर डालें, तो कुल 1,465 सहकारी बैंक हैं, जिनमें से 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा शहरी सहकारी बैंकों वाला कोई राज्य है, तो वह महाराष्ट्र है। अमित शाह ने सहकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के सरकार के फैसले को रेखांकित करते हुए घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। सीआरसीएस (Central Registrar of Co-operative Societies) का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खुलेगा। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश भर में सहकारी बैंकों को समर्थन देने के लिए अपनी सरकार के एक प्रमुख पहल पर

चर्चा की। उन्होंने कहा, हम एक UMBRELLA संगठन को सक्रिय कर रहे हैं, जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा। UMBRELLA संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के बालेवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कराई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 20 लाख लाभार्थियों को आवास के लिए मंजूरी पत्र प्रदान किए गए, जबकि 10 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त जारी की गई। अमित शाह ने योजना की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक साथ 20 लाख लाभार्थियों को अपना खुद का घर मिलने का आनंद

एक ही क्षण में आया। 10 लाख लाभार्थियों को घर बनाने के लिए पहली किश्त कार्यक्रम समाप्त होने के पहले देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। सभी लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अमित शाह ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया कि 10 लाख लाभार्थियों की पहली किश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। राहुल गांधी की याद आई। उन्होंने कहा था आप सबको अकाउंट देंगे। लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर क्या करोगे? राहुल बाबा आज यह मोदी का चमत्कार देखो। दस लाख लोगों को पहली किश्त सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। दस लाख लोगों को एक साथ किश्त देने का कार्यक्रम और 20 लाख लोगों को घर आवंटित करने का कार्यक्रम। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की जनता प्रामाण्य से 20 लाख लाभार्थियों को आवास के लिए मंजूरी पत्र प्रदान किए गए, जबकि 10 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र को मिले हैं। घर का मतलब सिर्फ चार दीवारों नहीं है। घर का मतलब विकास के स्वप्न को सार्थक करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, महायुक्ति सरकार ने बहुत सारे काम महाराष्ट्र के विकास के लिए किए हैं। आज यहां पर मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। >10

तेलंगाना में बड़ा हादसा, टनल का हिस्सा धंसने से दो इंजीनियरों सहित 8 फंसे, बचाव कार्य जारी

हैदराबाद, 22 फरवरी (शुभ लाभ ब्यूरो)। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर की सुरंग के अंदर रॉबिन्स टनल बॉरिंग मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी के दो इंजीनियरों सहित आठ लोगों के फंसे होने की पुष्टि हुई है। यह सुरंग आज सुबह नागरकुरनूल के अमराबाद मंडल के डोमलपेटा के पास ढह गई। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के साथ दुर्घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार फंसे हुए श्रमिकों को बचाने और उन्हें जीवित बाहर निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चल रहे बचाव अभियान में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की मदद ली जा रही है।



और चार मजदूर शामिल हैं। एक इंजीनियर यूपी के चंदौली जिले का रहने वाला है। टनल में फंसे मजदूरों के नाम हैं - मनोज कुमार, श्रीनिवास, संदीप साहू, जगता एक्सेस, संतोष साहू, अनुज साहू, सनी सिंह, गुप्रित सिंह। >10

प्रधानमंत्री मोदी ने एसएलबीसी सुरंग बचाव अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया हैदराबाद, 22 फरवरी (शुभ लाभ ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरकुरनूल जिले के डोमलपेटा के पास एसएलबीसी सुरंग में हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रवंत रेड्डी से बात की। सीएम रवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि सुरंग के अंदर अभी आठ मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक बचाव उपाय शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और जुपल्ली कृष्ण राव चल रहे बचाव अभियान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रवंत रेड्डी को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बचाव प्रयासों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम तुरंत तैनात की जाएगी। तेलंगाना सरकार, केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में, फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास कर रही है। शनिवार रात को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अधिकारियों को राज्य और केंद्रीय दोनों टीमों के सहयोग से सफल परिणाम की उम्मीद है।

पंजाब में मंत्रालय फर्जीवाड़ा! घिर गई भगवंत मान सरकार

मंत्री को ऐसा विभाग सौंपा जो था ही नहीं, 20 महीने बाद पता चला नई दिल्ली, 22 फरवरी (एजेंसियां)। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपनी ही सरकार में कामेडी हो गई। असल में हुआ यूँ कि पंजाब में एक बड़े मंत्री को सौंपा गया विभाग अस्तित्व में ही नहीं था और सरकार को इसके बारे में 20 माह बाद पता चला। इसके बाद इस विभाग को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन में ये स्वीकार किया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग अस्तित्व में ही नहीं था। यह विभाग कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के पास था, जिसके चलते उनके विभाग वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया गया है। अब कुलदीप सिंह धालीवाल सिर्फ एनआरआई मामलों के मंत्री होंगे। धालीवाल के पास शुरू में कृषि और किसान कल्याण विभाग भी था लेकिन मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान उनसे ये प्रभार ले लिया गया। उस समय उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग भी आवंटित किया गया। सितंबर 2024 के कैबिनेट फेरबदल में ही उनके पास ये विभाग था। हालांकि सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए मंत्री कुलदीप धालीवाल को न तो कोई स्टाफ आवंटित किया गया और न ही इस विभाग की कोई बैठक हुई। >10

पैसा था वन संरक्षण के लिए और खरीदी गई लैपटॉप-टैबलेट के साथ कई अन्य चीजें

नई दिल्ली, 22 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से दौरान सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बजट की भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपये का दुरुपयोग और गलत तरीके से रकम को खर्च करने के मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में वन संरक्षण के लिए खर्च किए गए फंड में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग द्वारा वन संरक्षण के लिए निर्धारित फंड का इस्तेमाल लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, फ्रीज और ऑफिस के लिए सजावट के सामान खरीदने में किया गया। यह रकम करोड़ों रुपये में थी, जो इस उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से अनुचित तरीके से खर्च की गई। 2022 के रिकॉर्ड की जांच में कई ऐसे उदाहरण सामने आए



हैं, जहां कैपा (प्रतिभूक्त वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) फंड का इस्तेमाल वनीकरण कार्यों के बजाय अन्य कामों के लिए किया गया। कैपा को मिलने वाली फंड का उपयोग एक साल के भीतर करना होता है, लेकिन रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि 37 मामलों में इन फंड का उपयोग करने में 8 साल का समय लग गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सड़क, पावर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, रेलवे और ऑफ रोड लाइन के लिए औपचारिक सहमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद डिवीजनल फॉरेस्टर अफसर (डीएफओ) की मंजूरी नहीं ली गई थी। 2017 से 2022 के बीच 52 मामलों में डीएफओ की मंजूरी की अनदेखी की गई थी। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना के तहत 56.97 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया, जबकि यह पैसा किसी अन्य उद्देश्य के लिए था। इसके अलावा, अल्मोड़ा कार्यालय में बिना मंजूरी के सोलर फेंसिंग पर 13.51 लाख रुपये खर्च किए गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जन जागरूकता अभियान के लिए निर्धारित 6.54 लाख रुपये का उपयोग मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता और कानूनी प्रकोष्ठ के लिए ऑफिस बनाने पर किया गया। इसके अलावा, 13.86 करोड़ रुपये का दुरुपयोग अन्य विभागीय परियोजनाओं में किया गया, जिसमें टाईगर सफारी परियोजनाएं, कानूनी शुल्क, व्यक्तिगत यात्रा और आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, और कार्यालय आपूर्ति जैसी वस्तुओं की खरीद शामिल थी।

पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव-2 नियुक्त

नई दिल्ली, 22 फरवरी (एजेंसियां)। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी-2 नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगी। वह दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, और 10 दिसंबर 2024 का उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। आदेश के मुताबिक, वह प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी-1 डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। केंद्र सरकार में अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास, आईएएस (रिटायर्ड) (टीएन:80) की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जारी रहेगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से ताल्लुक रखने वाले 67 वर्षीय शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने केंद्र और तमिलनाडु सरकारों के लिए विभिन्न पदों पर काम किया है। केंद्र में उन्होंने विभिन्न चरणों में आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और फॉरटिलाइजर सेक्रेटरी के रूप में काम किया। वह दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। >10



लिए ऑफिस बनाने पर किया गया। इसके अलावा, 13.86 करोड़ रुपये का दुरुपयोग अन्य विभागीय परियोजनाओं में किया गया, जिसमें टाईगर सफारी परियोजनाएं, कानूनी शुल्क, व्यक्तिगत यात्रा और आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, और कार्यालय आपूर्ति जैसी वस्तुओं की खरीद शामिल थी। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2017 से 2022 तक हुए वृक्षारोपण में से करीब 33 फीसदी पौधे ही जिंदा रह पाए। यह वन अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्धारित पौधों के जीवित रहने की दर 60-65 फीसदी से कम है। इसके कई परिणाम सामने आए हैं। सबसे पहले, वृक्षारोपण खड़ी और चट्टानी ढलानों पर किया गया, जिसके कारण पेड़ों का जीवित रहना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, क्षेत्र में मौजूद बड़े देवदार के पेड़ों ने नए वृक्षारोपण के विकास में रुकावट पैदा की। साथ ही, सुरक्षात्मक उपायों के अभाव >10

सर्साफ़ा बाज़ार

सोना : 88,940/- (प्रति 10 ग्राम)

चाँदी : 99,099/- (प्रति किलोग्राम)

मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 33°

न्यूनतम : 23°

कश्मीर के मूल निवासियों का संकट बरकरार

सुरेश एस डुग्गर जम्मू, 22 फरवरी। कश्मीर वादी के मूल निवासी कश्मीरी पंडित परिवारों की संख्या में गिरावट जारी है। 2024 तक केवल 728 परिवार बचे हैं, जो 2021 में 808 परिवारों से कम है। गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (केपीएसएस) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है जो इस कमी में योगदान दे रही हैं। सर्वेक्षण में आर्थिक

कश्मीरी पंडितों से खाली न हो जाए कश्मीर वादी

नहीं ढूँढ पाए हैं। कम परिवारों के साथ, युवाओं के लिए समुदाय के भीतर मैच ढूँढना मुश्किल होता जा रहा है, और अंतर-समुदाय विवाह दुर्लभ हैं। घटती आबादी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। हिंदू पुजारियों की भारी कमी ने पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना मुश्किल बना दिया है, कई परिवार अब विशेष कश्मीरी पंडित परंपराओं के बजाय व्यापक हिंदू प्रथाओं को अपना रहे हैं। जीवन की घटनाओं, जन्म और मृत्यु-के संतुलन में व्यवधान ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे दशकों पुराने प्रयास नौकरशाही की बाधाओं के कारण विलंबित हो गए हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक अविवाहित कश्मीरी पंडित युवाओं की बढ़ती संख्या है। टिक्कू बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों को सरकारी लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसआरओ 425 के तहत रोजगार और पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के उनके

समुदाय के लिए अपने रीति-रिवाजों को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। हाल ही में, मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वास-निर्माण प्रयासों का आह्वान किया। टिक्कू ने इस भावना का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुलह के प्रयासों को दोनों समुदायों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। टिक्कू कहते हैं कि मीरवाइज का आह्वान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन नागरिक समाज के स्तर पर 2010 में पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं। >10





विपक्ष की गलत सूचना के बावजूद कर्नाटक की अर्थव्यवस्था मजबूत: सीएम सिद्धरामैया

अगर वे अत्याचार करेंगे तो हम उन्हें उचित सबक सिखाएंगे : कर्नाटक रक्षण वेदिके

बंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत वित्तीय कुप्रबंधन के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अलग तस्वीर पेश करने के प्रयासों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भाजपा नेताओं, जिनमें राज्य इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हैं, के आरोपों का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने विपक्ष पर आर्थिक पतन के झूठे दावों के साथ जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने कहा उनके बयानों के विपरीत, कर्नाटक की अर्थव्यवस्था स्थिर है और आगे बढ़ रही है। वास्तविक वित्तीय तनाव भाजपा के शासन में हुआ, जिसने सार्वजनिक कार्यों, सिंचाई और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 2.70 लाख करोड़ रुपये के अवैतनिक बिलों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने उचित बजटीय आवंटन के बिना 1.66 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सीएम ने इस बात



पर प्रकाश डाला कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान, आर्थिक कुप्रबंधन ने कर्नाटक को वित्तीय अस्थिरता की ओर धकेल दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शासन में पिछले दो वर्षों में राज्य की औसत बजट वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही है, जो भाजपा के चार साल के शासन के दौरान दर्ज की गई 5 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक है। सिद्धरामैया ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया, जीएसटी मुआवजे की वापसी के कारण 18,000-20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होने का हवाला

यह सम्मान का पैसा है
इससे पहले सांसद बसवराज बोम्मई ने गारंटी की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए एक योजना है। यह लोगों और मालाओं की आंखों में धूल झांकने की योजना है। वे पूछते हैं कि गृहलक्ष्मी का पैसा वेतन है या नहीं। यह सम्मान का पैसा है। अगर यह हर महीने नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका सम्मान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार लड़कियों का सम्मान करने में विफल रही है। किसी भी महीने गृहलक्ष्मी का पैसा ठीक से नहीं आया है। राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि, सीएम अहंकार के कारण इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां शुकुवार को पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा केवल गारंटी ही नहीं, बल्कि किसी भी विकास परियोजना के लिए पैसा नहीं है। ऋण आधारित परियोजनाओं को छोड़कर, कुछ भी नहीं है। उन्होंने पेयजल परियोजना के लिए पैसा न देकर लोगों को परेशानी में डाल दिया है। आम लोगों के इस्तेमाल की सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। वे कर वसूलने और गारंटी के रूप में उसे वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस अपनी प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए उदयनगर दंगों और मैसूरु में आंतरिक अशांति की बात कर रही है। वह विकास नहीं करना चाहती।

भाजपा पर सत्ता में रहते हुए कर्नाटक को विफल करने और अब गलत सूचना का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा उनकी साजिशों के बावजूद कर्नाटक मजबूती से खड़ा है। हम लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं और केंद्र से राज्य के हक का हिस्सा



बंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने कहा कि कन्नड़ सीखें और कन्नड़ की तरह जियें। साथ ही उन्होंने दूसरे राज्य के कन्नड़ विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वे हिंसा का सहारा लेंगे तो उन्हें उचित सबक सिखाया जाएगा। मंच के राज्य अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बेलगावी में मराठी में बात न करने पर सरकारी बस कंडक्टर पर हुए हमले के संबंध में चेतावनी जारी की है। मराठी गुंडों ने महादेव नामक एक बस कंडक्टर पर इसलिए क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया क्योंकि वह मराठी के बजाय कन्नड़ में बात कर रहा था। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेलगावी पुलिस को महादेव पर हमला करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। कन्नड़ लोग मित्रवत और शांतिप्रिय हैं और हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो बिना कारण हम पर हमला करते हैं। उन्होंने इस बात पर अपना आक्रोश व्यक्त किया कि भाषा के प्रति जुनूनी मराठी गुंडों ने बेलगावी को उनसे छीनने के अपने

सभी प्रयास विफल होने के बाद और अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। उसने साहसी काम किया है। केएसआरटीसी के चालकों और परिचालकों को इस घटना से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे कार्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग कर्नाटक की धरती पर रहते हैं उन्हें कन्नड़ सीखना चाहिए और कन्नड़िगा की तरह रहना चाहिए। इसके अलावा, यदि वे अपनी भाषा सीखने की चेतावनी देकर अत्याचार करना शुरू करते हैं, तो कर्नाटक रक्षण वेदिके उन्हें करारा सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि यह मेरी सीधी चेतावनी है।

मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बोम्मई से किया सवाल बजट आकार से सात गुना अधिक लागत के कार्यों को मंजूरी देना कितना सही

बंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने तत्कालिन भाजपा सरकार पर राज्य की जनता पर बजट आकार से सात गुना अधिक लागत के कार्यों को मंजूरी देने के लिए निशाना साधा है। साथ ही आश्वासन दिया है कि भाजपा सत्ता में वापस नहीं आएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब बसवराज बोम्मई सर्व सम्पन्न जैसी बातें कर रहे हैं। बोम्मई, जो कहते हैं कि हमारी सरकार लोगों के साथ गलत कर रही है, अगर उनमें कम से कम अंतरात्मा होती, तो वे ऐसा नहीं बोलते। बोम्मई, आपने मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया है? अगर हम पूछेंगे तो आप जवाब देने में हिचकिचाएंगे। जब आप मुख्यमंत्री थे तो इस राज्य के लिए आपका क्या योगदान था? क्या आप जवाब देंगे? बोम्मई, मुझे यह सच्चाई पता थी कि आप 2023 में सत्ता में नहीं लौटेंगे। तो, पद छोड़ने से पहले, आपने बजट लागत से 7 गुना



अधिक लागत वाले कार्यों को मंजूरी दी। काम करने वाले ठेकेदार को भुगतान क्यों करेगा? क्या आपको इस बात का अहसास नहीं था कि आपने अपने खजाने से अप्रासंगिक कार्यों के भुगतान को मंजूरी दी थी? क्या यह लोगों के मुंह में कीचड़ डालना नहीं है? बोम्मई, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो क्या आपने कभी केंद्र सरकार के कर अन्याय के बारे में आवाज उठाई थी? क्या आपने कभी मोदी सरकार द्वारा राज्य के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में आवाज उठाई है? क्या मोदी के सामने पीठ

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार शाम को दावा किया कि भारत को चुनाव फंडिंग के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई टिप्पणी और बाद में इस सहायता को बंद करने से उन आरोपों की पुष्टि होती है कि वामपंथी और कांग्रेस देश की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ काम कर रहे थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा हमें नहीं पता कि इतनी बड़ी धरणाशिया क्यों दी गई। इससे पहले हमारे एक सांसद ने भी इसका जिक्र किया था। उस समय आरोप था कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बाहरी मदद मांगी थी। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और उसके बाद इस सहायता को रोकना उन आरोपों की पुष्टि करता है। जोशी ने आरोप लगाया वामपंथी और कांग्रेस भारत के चुनावों को प्रभावित

ट्रंप के बयान का मामला प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस और वामपंथियों पर विदेशी मिलीभगत का आरोप लगाया



करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। मंत्री ने विदेशी ताकतों की कथित संलिप्तता की निंदा करते हुए कहा यह इन दलों द्वारा किया गया सबसे शर्मनाक कृत्य है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यहां तक कि सैम पित्रोदा के बयान को लेकर भी वे अब खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी उनके लिए परिस्थिति कठिन होती है, तो वे ऐसा ही करते हैं। जोशी ने कांग्रेस

हालिया समय की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बाहरी एजेंसियों और विदेशी फंड का इस्तेमाल करने का प्रयास करती रही है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। बंगलूरु में भाजपा की बैठक के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने स्पष्ट किया कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा चूंकि मुझे चंडीगढ़ जाना है, इसलिए मैं बंगलूरु नहीं जाऊंगा। राज्य के नेताओं को कर्नाटक में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई में रणनीति तय करेंगे। ग्रेटर बंगलूरु परियोजना के मुद्दे पर जोशी ने कहा विरोध जताते हुए कहा, हम ग्रेटर बंगलूरु की अवधारणा का कड़ा विरोध करते हैं। दिल्ली में हमारा अनुभव, जिसे चार भागों में विभाजित किया गया था, विफल साबित हुआ है। अन्य शहरों में भी इसी तरह का विभाजन असफल रहा है। इस संदर्भ में, हम इसका विरोध करते हैं। हम बंगलूरु का समर्थन करते हैं, जैसा कि इसके संस्थापक केम्पे गौड़ा ने कल्पना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2012 में भारत में मतदान के लिए यूएसएआईडी द्वारा दिए गए 21 मिलियन डॉलर के फंड पर सवाल उठाया है, इसे रिश्तत योजना कहा है। रिपब्लिकन गवर्नरों से बात करते हुए, ट्रंप ने अपने दावों के लिए कोई सबूत दिए बिना कहा, मुझे क्या परवाह है? हमारे पास अपनी खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस तरह के फंड अक्सर उन्हें आवंटित करने वालों को वापस दिए जाते हैं और उन्होंने बंगलादेश में राजनीतिक सुधारों के लिए 29 मिलियन डॉलर के अनुदान पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन ने इन खर्चों को समाप्त कर दिया है, उन्हें बेकार करार दिया है।

राज्य सरकार ने गारंटी योजनाओं को नहीं किया है बंद: सतीश जारकीहोली

एक सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी गृह लक्ष्मी निधि: मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर

बंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि राज्य सरकार ने गारंटी योजनाएं बंद नहीं की हैं। गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को पैसा देने में कुछ महीनों की देरी हो सकती है। आने वाले दिनों में दोनों महीनों का पैसा एक साथ मिल सकता है। यहां शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा सरकार के स्तर पर फंड देने में देरी होना स्वाभाविक है। देरी के बावजूद पैसा देना बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा डी.के. शिवकुमार शुरू से ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सीएम और केपीसीसी अध्यक्ष के बदलाव पर हाईकमान फैसला लेगा। मैं केपीसीसी अध्यक्ष पद का आकांक्षी नहीं हूँ। समय आने पर अगला फैसला लूंगा। केपीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार हमारे



पास नहीं है, यह हाईकमान देखता है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केपीसीसी अध्यक्ष में बदलाव होगा। यह तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में होगा। उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कब होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र की भाजपा सरकार मुझा मामले में ईडी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इसे साबित नहीं किया जा सकता। कोई सबूत नहीं है। सीएम की 14 साइटें ही राजनीति में सबसे ज्यादा कृप्या को नोटिस्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम सिद्धरामैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र के खिलाफ आरोपों को साबित करने

सौपी। अदालत ने अगली सुनवाई आगामी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। पुलिस ने 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और 27 खंडों वाली 11,200 पृष्ठों वाली जांच रिपोर्ट को भी रिपोर्ट बताया है। जांच में पाया गया कि साइट आवंटन घोटाले में अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार के सदस्यों को क्लीन चिट दे दी है, जिससे राज्य की राजनीति में भारी हलचल मच गई है। मामले की जांच करने वाले मैसूरु के लोकायुक्त एस.पी. उदेश ने गुरुवार को बंगलूरु स्थित विशेष जनप्रतिनिधि न्यायालय के न्यायमूर्ति संतोष गजानन भट की पीठ को सीलबंद लिफाफे में लगभग 11,200 पृष्ठों की रिपोर्ट

के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले कर्नाटक लोकायुक्त ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार के सदस्यों को क्लीन चिट दे दी है। सिद्धरामैया को मामले में पहला आरोपी बनाया गया था, जबकि उनकी पत्नी बी एम पार्वती और उनके साले मल्लिकार्जुनस्वामी को क्रमशः दूसरा और तीसरा आरोपी बनाया गया था। भूस्वामी जे देवराजू को चौथा आरोपी बनाया गया था। आरोपों में दावा किया गया था कि सिद्धरामैया ने 3.16 एकड़ भूमि के बदले में मुडा से अपनी पत्नी के नाम पर 14 साइटों का आवंटन धोखाधड़ी से हासिल किया। हालांकि, जांच के बाद लोकायुक्त ने सभी आरोपियों को गलत काम करने से मुक्त कर दिया।



बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने घोषणा की कि गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के लिए निधि एक सप्ताह के भीतर उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। बेलगावी में अपने गृह कार्यालय में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि निधि तालुक पंचायतों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया राशि वितरित करने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि मैं सड़क दुर्घटना के कारण आराम कर रही थी। हालांकि, मैंने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, और जल्द ही निधि जमा कर दी जाएगी। अब तक, निधि बंगलूरु में केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से वितरित की जा रही थी। हालांकि, विकेंद्रीकरण प्रयास के हिस्से के रूप में, सरकार ने



विश्वविद्यालयों को बंद करने का निर्णय मूर्खता की पराकाष्ठा

सरकार विश्वविद्यालयों को बंद करने के बजाय जिलों में शिक्षा सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे: विजयेन्द्र

सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत



उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो।

परकला मुख्य सड़क पर एक दुर्घटना में एक कार चालक की मौत हो गई, जो सड़क पार करते समय दूसरे वाहन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान रमेश नायक (55) के रूप में हुई है। वह अपनी गाड़ी पार्क करके एक दुकान के पास सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, जहां वह कुछ देर के लिए रुका था, तभी उसे एक तेज रफतार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका शरीर काफी दूर तक घसीटा गया और उसके जूते सड़क पर बिखरे मिले। उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे काफी खून बह गया और खून के छींटे सड़क के दूसरी तरफ तक पहुंच गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह स्थान एक कुख्यात ब्लैक स्पॉट

बन गया है, जहां कई पैदल यात्रियों की मौत की खबरें हैं। केंद्रीय डिवाइडर की अनुपस्थिति और टेकेदारों द्वारा अधूरे सड़क निर्माण कार्य ने क्षेत्र में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या में योगदान दिया है। इस जंक्शन पर अब तक कम से कम पांच पैदल यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। शेदिडु निवासी रमेश नायक अपनी पत्नी को ड्यूटी के लिए पास के अस्पताल में छोड़कर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिवमोग्गा की ओर जा रही तेज रफतार कार ने नायक को सड़क पार करते समय टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने घायल व्यक्ति को उसी वाहन से मणिपाल अस्पताल पहुंचाने में मदद की जिसने उसे टक्कर मारी थी।



चाहिए। अन्यथा राज्यव्यापी संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। सरकार का यह फैसला शर्मनाक है। राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लोगों पर ऊंचे कर थोपने और गारंटी खत्म न होने देने का प्रयास कर रही सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए स्थापित विश्वविद्यालयों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सीएसआर अनुदान और

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए उनका विकास किया जाए। इस बीच, उन्होंने विश्वविद्यालय बंद होने की निगरानी के लिए गठित उपसमिति पर सवाल उठाए और समिति में अकादमिक विश-षज्ञों की कमी पर चिंता व्यक्त की। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसकी उप-समिति ने

विश्वविद्यालयों को बंद करने का सुझाव दिया था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि खराब गुणवत्ता वाले निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विकेंद्रीकरण के बाद विश्वविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों को बंद करने से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को लाभ होगा। जो विश्वविद्यालय

पीड़ित किसानों की पीड़ा को कम करना होगा

इससे पहले विजयेन्द्र ने कहा था कि राज्य सरकार को जागने की जरूरत है। हमें गारंटी के भ्रम से उबरना होगा और बिजली की समस्या से पीड़ित किसानों की पीड़ा को कम करना होगा। पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छह से सात घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में असमर्थ है। किसानों को बिजली कब मिलेगी? ऐसा लगता है जैसे आपको कभी पता ही नहीं कि यह कब चला जाएगा। विभाग का कहना है कि वे रात 10 बजे से बिजली उपलब्ध कराएंगे। किसानों ने शिकायत की कि वे खेतों में काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने किसानों को संकट में डालने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार को बिजली की कमी होने पर अन्य राज्यों से खरीद की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। बिजली कटौती के कारण किसानों को और अधिक कठिनाई में नहीं धकेला जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए।

अब बंद होने वाले हैं वे चामराजनगर, हावेरी और कोपल जिलों में हैं, जहां लोगों को पहले से ही शिक्षा तक पहुंच नहीं है। अभी विश्वविद्यालयों को बंद करने से स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए सरकार विश्वविद्यालयों को बंद करने के बजाय जिलों में शिक्षा सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे।

मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए संगठित प्रयास: सांसद मंजूनाथ

भाजपा गुटबाजी के बीच हार्डकमान का फैसला होगा दिलचस्प

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

बेंगलूरु ग्रामीण के सांसद डॉ. सी.एन. मंजूनाथ ने कहा मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देने का मुद्दा लाया है, जिसे राज्य द्वारा बेंगलूरु और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल समस्या को हल करने के लिए तैयार किया गया है। राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौडा, जो जेडीएस सुप्रोमो भी हैं, ने भी सत्र में परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

विभिन्न कारणों से अनुमति में देरी हुई है। हालांकि, हम राजनीतिक मतभेदों को अलग रख रहे हैं और परियोजना को लागू करने के लिए टोस प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नवीनतम बजट में, स्वास्थ्य, संरक्षण, कृषि उत्प-ादकता और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की सीधी सहायता प्रदान की जा रही है। रागी और धान सहित 23 कृषि



उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत रामनगर जिले में 2.60 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। जनधन योजना के तहत देशभर में 73 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। देश में यूरिया उत्पादन को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने बजट में असम में 22 लाख टन यूरिया उत्पादन का कारखाना शुरू करने की घोषणा की है। इससे निजी कारखानों पर निर्भरता कम होगी। यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेलवे के लिए राज्य को 835 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में 7,564 करोड़ रुपये जारी किए गए और विभिन्न कार्य किए गए।

चन्नपटना और रामनगर रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के लिए 51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बिदादी रेलवे स्टेशन के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही सरकार ने उन्हें अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की है। हरोहल्ली के लिए पहले से ही घोषित ईएसआई अस्पताल की आधारशिला जल्द ही रखी जाएगी। पीएम योजना के तहत देश में और अधिक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक भाजपा में मंचे घमासान के बीच विपक्षी गुट ने खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष पद को बदलने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेन्द्र को बदलने की मांग की है। लेकिन राज्य भाजपा में मंचे घमासान के बीच अब पार्टी आलाकमान ने अहम फैसला लिया है। इस बीच, क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयेन्द्र को बढ़त मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद भाजपा विधायक बसन्तगौड़ा पाटिल यतनाल के नेतृत्व वाली बागी टीम पूरी तरह से शांत हो गई है और यतनाल का अगला कदम भी कौतूहल का विषय बन गया है।

कमल खेमे में चर्चा चल रही है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए चुनाव कराया जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, असंतुष्टों के विरोध के बावजूद, कर्नाटक में नई परंपरा शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए उसने वर्तमान अध्यक्ष बी.वाई. विजयेन्द्र



को ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जारी रखने का फैसला किया है। भाजपा के इतिहास में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए होड़ का उदाहरण पहले कभी नहीं रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा आलाकमान ने इस परंपरा को न तोड़ने का फैसला किया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मतपत्र करने की मांग की है। विपक्ष के बीच भाजपा विधायक बसन्तगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा बी.वाई. विजयेन्द्र के खिलाफ एक सक्षम नेतृत्व वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर चर्चा चल रही है। इस मुद्दे को लेकर रमेश जाकरहीली और बसन्तगौड़ा

पाटिल यतनाल के नेतृत्व वाले गुट में महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। इस प्रकार, कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की संभावना दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, और कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने वर्तमान अध्यक्ष बी.वाई. विजयेन्द्र को अगले तीन साल के कार्यकाल के लिए जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। यह लगभग तय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बिना चुनाव के ही होगी। इस बात की प्रबल संभावना है कि विजयेन्द्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अब चूंकि नेता प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए सवाल

यह उठ खड़ा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब यह समझा जा रहा है कि विजयेन्द्र के इस पद पर बने रहने की अधिक संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया इस महीने के अंत तक होगी। इसके तहत 50 प्रतिशत राज्यों में अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कई राज्यों में जिला एवं प्रदेश अध्यक्षों की सूची प्रकाशित की जाएगी। साथ ही, इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह में की जाएगी, जो कि बसन्तगौड़ा पाटिल यतनाल और उनकी टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो विजयेन्द्र में बदलाव के लिए दबाव बना रहे थे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के गृह निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपुरा से पहली बार जीते विधायक विजयेन्द्र के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लोहे की मुड़ी की तरह थी। कमल खेमे में गुटबाजी की राजनीति पर विराम लगाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक में भाजपा के संगठनात्मक चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है। इस बीच, कहा

जा रहा है कि विजयेन्द्र द्वारा यह विश्वास जताए जाने के बाद कि वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सत्ता में बने रहेंगे, भाजपा नेता जल्द ही चुनावों पर रोक लगाने की योजना बना रहे हैं। यतनाल, जो विजयेन्द्र के खिलाफ ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अचानक चुप हो गए हैं। दो दिन पहले ही यतनाल ने मीडिया पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि सभी नोटिस विजयेन्द्र द्वारा बनाए गए हैं। क्या आपने नोटिस का जवाब दिया का सही उत्तर दिए बिना ही चले गए। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि रिबेल टीम को एक बड़ा झटका होगा, जो यतनाल के नेतृत्व में विद्रोही टीम ने अगली लड़ाई पर चर्चा की। लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन आलाकमान से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने से विद्रोही टीम में निराशा भी पैदा हुई है। यह स्पष्ट है कि विजयेन्द्र अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं, भले ही यतनाल और उनकी टीम सीधे तौर पर विजयेन्द्र पर हमला कर रही है। यह स्पष्ट है कि विजयेन्द्र चुपचाप अपनी रणनीति पर प्रयोग कर रहे हैं।

अपमानजनक टिप्पणी को लेकर प्रताप सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज



मैसूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

शहर युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष सैयद अबरार ने पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ उदयगिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है। शिकायत में कहा गया है कि प्रताप सिन्हा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि मुस्लिम समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है और अधिक बच्चे पैदा कर रहा है। उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों का अपमान हुआ।

राजभवन बनाम सरकार के बीच फिर टकराव?

तीन विधेयक लौटा दिए

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

आने वाले दिनों में राजभवन और सरकार के बीच टकराव और विधायिका और कार्यपालिका के बीच लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल की शक्तियों को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है तथा उन्हें कुछ विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों के मुख्य अतिथियों तक सीमित कर दिया है। इससे नाराज राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सरकार द्वारा भेजे गए तीन विधेयक लौटा दिए हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को सरकार को लौटाते हुए कहा कि यह संशोधन भ्रामक है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन लाने की बजाय सत्ता हथियाने का प्रयास है। उन्होंने जो अन्य दो विधेयक वापस भेजे, वे थे मैसूरु प्राधिकरण विकास विधेयक-2024 और कर्नाटक वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2024। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने राज्य में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए बिना और कई स्पष्टीकरण मांगे बिना उसे वापस भेज



दिया था। अध्यादेश केवल उधारकर्ताओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। सामान्य कानून के अंतर्गत उधारदाताओं को कोई संरक्षण नहीं है। यह दीर्घकाल में घातक होगा। माइक्रोफाइनेंस 3 लाख रुपये से अधिक का ऋण प्रदान नहीं करता है। राज्यपाल ने सरकार से पूछा था कि वे पांच लाख रुपये का जुर्माना कैसे लगाएंगे। सामान्यतः, राज्यपाल प्रत्येक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते थे। राज्यपाल कुछ प्रशासनिक निर्णय लेते थे, जिनमें कुलपतियों की नियुक्ति, सिंडिकेट सदस्यों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों में कार्य का प्रबंधन शामिल था। यह स्पष्ट है कि जब भी सरकार ने धीरे-धीरे राज्यपाल की शक्तियों में कटौती शुरू की, राज्यपाल ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आखिरकार, राज्यपाल द्वारा भेजा गया कर्नाटक ग्रामीण

विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बेलगावी में शीतकालीन सत्र में पारित हो गया। अब तक राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते थे। लेकिन संशोधित संस्करण में मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और सिंडिकेट सदस्यों सहित प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय उनकी जिम्मेदारी है। अर्थात् राज्यपाल के पास जो शक्तियाँ थीं, उन्हें धीरे-धीरे सरकार छीन रही थी और केवल इन विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाले वार्षिक दीक्षांत समारोहों में ही राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती थीं। इससे पहले, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सहित कुछ ही राज्यों की सरकारों और राजभवन के बीच टकराव चल रहा था। ऐसे भी आरोप लगे हैं जहां कुछ राज्यपाल, जिनमें वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनकड़, तमिलनाडु

के रवि और केरल के आरिफ मोहम्मद खान शामिल हैं, यह भूल गए कि वे कार्यपालिका के प्रमुख हैं और उन्होंने पार्टी के मुखपत्र की तरह व्यवहार किया है। विशेष रूप से, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार द्वारा भेजे गए कई विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस लौटा दिया। अंततः मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से राज्यपाल को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी कि वे आग से न खेलें। अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में ऐसे कई राज्यपालों के उदाहरण हैं जिन्होंने अनुकरणीय शासन दिया है। जब बी.एस. येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब हंसराज भारद्वाज के व्यवहार को लेकर सार्वजनिक स्तर पर आलोचना हुई थी। वजुभाई वाला, के. रोसेया, रामेश्वर ठाकुर, टी.एन. चतुर्वेदी, रमादेवी, खुशींद आलम खान आदि सहित कई लोगों ने बिना किसी विवाद के शासन किया और प्रसिद्ध हुए। राजभवन और विधायिका के बीच टकराव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, जब से राज्यपाल ने कैबिनेट के फैसले की अवहेलना करते हुए मुद्दा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।

भाषा को लेकर विवाद के बाद बस चालक और कंडक्टर पर हमला, 4 गिरफ्तार

बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो।

उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के बस चालक और कंडक्टर पर बेलगावी में भाषा को लेकर विवाद के बाद युवकों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को सुलेभवी के पास हुई। अर्बन सीबीटी-सुलेभवी बस में सवार एक लड़के और लड़की ने कथित तौर पर कंडक्टर को धमकाया क्योंकि वह मराठी में बात नहीं कर पा रहा था, और इसके बाद, उन्होंने अपने साथियों को बुलाया जिन्होंने बालेकुंडरी में उन पर हमला किया। इससे तनाव बढ़ गया, जिसके कारण कंडक्टर पर हमला हुआ, और उसे अंदरूनी चोटें आईं। मारहल पुलिस ने हमले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मारुति तुरुमुरी, राहुल नायडू और बालू गोजागेकर शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रोहन जगदीश ने बेलगावी के बीआईएमएस अस्पताल का दौरा किया और कंडक्टर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कंडक्टर ने कहा कि मराठी न जानने के कारण उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि जब कंडक्टर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया तो उसे समझौता करने की सलाह दी गई। डीसीपी रोहन जगदीश ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि कन्नड़ भाषा, भूमि और जल की रक्षा करना हर कन्नड़िगा की जिम्मेदारी है और उन्होंने राज्य के सभी लोगों से भाषा सीखने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभाषा बोलना गर्व की बात होनी चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा हर किसी को कर्नाटक में रहने वाले लोगों के साथ कन्नड़ में बात करने का फैसला करना चाहिए। यह शपथ लेनी चाहिए कि कन्नड़ के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाएगी। कन्नड़ लोग उदार हैं। यही वजह है कि कर्नाटक में ऐसा माहौल है कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग भी कन्नड़ सीखे रह सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र या केरल जैसे राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जा सकती। वे सिर्फ अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। हमें भी अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। इस पर हमें गर्व होना चाहिए।

गोला में सीएम योगी ने रखी शिव मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला काशी विश्वनाथ धाम की तरह बनेगा भव्य कॉरिडोर

लखीमपुर खीरी, 22 फरवरी
(एजेंसियां)।

लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को न केवल शिव मंदिर कॉरिडोर बल्कि पूरे जिले के लिए 4500 करोड़ से अधिक की 373 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंदिर के प्रधान पुजारी दिनेश मिश्र की उपस्थिति में रामदेव मिश्र शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री से कॉरिडोर का शिलान्यास कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने राजेंद्र गिरि स्टेडियम में जनता का अभिवादन करते हुए सभा की।

मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि से पहले कॉरिडोर के शिलान्यास को स्वयं के लिए सौभाग्य का अवसर बताया। कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है। जिला खीरी अब पिछड़ा नहीं रहा। आने वाले दिनों में प्रदेश के विकसित जिलों में गिना जाएगा।

शनिवार को कुंभी में बलरामपुर



चीनी मिल में बनाए जा रहे 2850 करोड़ की लागत से देश के पहले बायोप्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास करके गोला में मुख्यमंत्री योगी पौराणिक शिव मंदिर पहुंचे। विधायक अमन गिरि, जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महाशिवरात्रि से पूर्व बाबा गोकर्णनाथ के दर्शन और बाबा

विश्वनाथ धाम की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का शिलान्यास का अवसर सौभाग्य से मिला है। लखीमपुर जिले में लगभग 4500 करोड़ की 373 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। रोजगार के क्षेत्र में 2850 करोड़ का पीएलए बायोप्लास्टिक प्लांट बलरामपुर चीनी मिल द्वारा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही लखीमपुर विकास में

काफी पिछड़ा था, लेकिन अब नहीं रहा। यहां अब दुधवा ही नहीं, छोटी काशी कॉरिडोर, पलिया में एयरपोर्ट बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जीवन को सुगम भी करेगा और रोजगार का सृजन भी होगा। अब खीरी विकास के साथ स्पिचुअल और इको टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है। खीरी में अब रोजगार की कमी नहीं रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि जनपद में बाढ़ की समस्या के स्थायी

समाधान के लिए प्रयास हो रहा है। नदियों को चैनलाइज किया जाएगा।

भारतीय रेलवे के माध्यम से जिले को कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। जो नए युग की शुरुआत है। थारू जनजाति की संस्कृति और उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सभा को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी संबोधित किया। संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ने 11:55 बजे प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया।

मुख्यमंत्री ने छोटी काशी के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि धार्मिक धरोहर एवं विरासत का जहां सुरक्षित किया जा रहा है, वहीं जीवन को सुगम बनाना सरकार का उद्देश्य है। कॉरिडोर निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को विस्थापित किया जाएगा। जिनका घर गया है, उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कॉरिडोर में दुकान बनवाकर दुकानदारों को भी विस्थापित किया जाएगा।

देश के बंदरगाहों को स्मार्ट बनाएगा कानपुर आईआईटी इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ हुआ समझौता



कानपुर, 22 फरवरी
(एजेंसियां)।

देश के बंदरगाहों को स्मार्ट बनाने का बीड़ा अब आईआईटी ने उठाया है। इसके लिए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) ने डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आईआईटी के सी3आई हब के साथ शनिवार को संस्थान परिसर में समझौता (एमओयू) किया है।

इसकी मदद से साइबर सुरक्षा नियंत्रण और प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया जाएगा।

एमओयू के तहत बंदरगाह अधिकारियों और परिचालन टीमों

के लिए विशेष साइबर सुरक्षा-संबंधी कौशल सेट विकसित करने और समुद्री क्षेत्र के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा नीतियों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित होगा। आईपीए के चेयरमैन सुनील पा-लीवाल ने कहा कि यह समझौता भारतीय बंदरगाहों को विश्वस्तरीय स्मार्ट बंदरगाहों में बदलने में सहायक होगा। इसका लक्ष्य न केवल स्वचालन को आगे बढ़ाना है, बल्कि डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा करने वाले मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को भी सुनिश्चित करना है। आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि

संस्थान को इस पहल का हिस्सा बनने पर गर्व है। आईपीए को सुरक्षित, स्मार्ट पोर्ट संचालन के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी विशेषज्ञता में सहयोग किया जाएगा।

सी3आई हब के प्रोजेक्ट निदेशक प्रो. संदीप शुक्ला ने कहा कि जैसे-जैसे बंदरगाह अधिक डिजिटल और स्वचालित होते जा रहे हैं, साइबर सुरक्षा को भी समानांतर रूप से विकसित किया जाना चाहिए। कहा कि लक्ष्य समुद्री परिचालन में साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना है।

संभल के बिजली चोर सांसद पर लगा 1.91 करोड़ का जुर्माना

संभल, 22 फरवरी (एजेंसियां)।

संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी में लगे 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माना मामले में 15 दिन का समय और मिल गया है। अब सात मार्च को सुनवाई होगी। बिजली विभाग से सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए शनिवार को प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर विभाग ने अब 15 दिन का समय और दे दिया है।

सात मार्च को अंतिम सुनवाई बताई जा रही है। इस तिथि तक सांसद को बिजली खपत के साक्ष्य देने हैं। यदि वह साक्ष्य नहीं देंगे तो अंतिम रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके अनुसार ही जुर्माना वसूलने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अधिशासी अभियंता (विद्युत) नवीन गौतम ने बताया कि तीन नोटिस और तीन रिमाइंडर सांसद को दिए जा चुके हैं। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम सुनवाई सात मार्च को तय की गई है। मालूम हो 19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिलने पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सांसद के आवास पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान

बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे मिले थे लेकिन इन मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बाईपास कर बिजली चोरी हो रही थी। मीटर की एमआरआई करने पर कई महीने की खपत जीरो पाई गई थी। उसके बाद ही बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी जुर्माने मामले में सुनवाई बिजली विभाग में चल रही है।

सांसद के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होनी है। सात दिन का समय दिया गया था। वह सोमवार को पूरा हो रहा है। यह भी अंतिम सुनवाई मानी जा रही है। तीन बार नोटिस दिया गया है और तीन बार समय बढ़ा दिया गया है। सांसद के मकान में हुए अवैध निर्माण मामले में नियत प्राधिकारी, उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा था कि बिना अनुमति निर्माण किया गया है। नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने एक सप्ताह का समय दिए जाने के साथ अंतिम बार समय बढ़ाने की बात कही थी। इस सुनवाई के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकुंभ में लगाई हाजिरी

महाकुंभ नगर, 22 फरवरी
(एजेंसियां)।

पवित्र त्रिवेणी संगम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सलुआ बाबा संग भी संगम स्नान किया। वहीं नड्डा परिवार ने गंगा मइया को चुनरी अर्पित करके लोककल्याण की कामना भी की।

जेपी नड्डा परिवार समेत शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने



उनका स्वागत किया। इसके उपरांत सभी नेतागण अरैल घाट से फ्लोटिंग जेटी के जरिए संगम पहुंचे।

यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने परिवार के साथ साइबरियन पक्षियों को दाना

खिलाया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भाजपा नेताओं संग सामूहिक रूप से संगम स्नान किया, तदोपरान्त पत्नी एवं परिजनों संग विधि-विधान संग संगम में पावन डुबकी लगाई। इस दौरान संगम स्नान करने पहुंची जनता ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय



अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जय श्रीराम और गंगा मइया की जय के जयघोष से अभिवादन किया। स्नानोपरान्त नड्डा परिवार, सीएम योगी और बीजेपी के अन्य नेत-ओं ने विधि-विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। यहां से सभी नेतागण बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां लेटे हनुमान जी की साविधि पूजा-अर्चना की। वहीं इसके बाद सभी ने अक्षयवट के भी दर्शन-पूजन किए।

विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने लगाई त्रिवेणी संगम में डुबकी महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे



महाकुंभनगर, 22 फरवरी
(एजेंसियां)।

तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य-भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने शनिवार को नया इतिहास रच दिया है। यहां अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम कर दी है। 60 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सहायिता बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में

कुल 120 करोड़ सनातनी हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में दुनिया के आधे से अधिक सनातनी त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाकर पुण्य फल प्राप्त कर चुके हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व तक यह संख्या 65 करोड़ से भी ऊपर पहुंच सकती है। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के सुव्यवस्थित प्रयासों से संभव हो पाया है। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

महाकुंभ के महाआयोजन में 73 देशों के राजनयिक और भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत तमाम देशों के अतिथि यहां अमृत स्नान करने पहुंचे। यही नहीं, मां

जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से अधिक लोग अब तक त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। भारत एक धार्मिक देश है। यहां एक नहीं, बल्कि कई धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी संख्या सनातन धर्म को मानने वालों की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 143 करोड़ (1.43 अरब) है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या लगभग 110 करोड़ (1.10 अरब) है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 120 करोड़ है। इस तरह अगर सनातनियों की संख्या की तुलना



दुनिया भर के सनातनियों की संख्या से की जाए तो 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। यदि देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो यह 55 प्रतिशत हो गई है। यानी देश की कुल जनसंख्या के करीब 55 प्रतिशत से ज्यादा लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं।

प्यू रिसर्च 2024 की रिपोर्ट मानें तो पूरी दुनिया में 120 करोड़ (1.2 अरब) आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है।

मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्राद्ध और आस्था से ओत-प्रोत साधु-संतों, श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान

अब उस शिखर के भी पार पहुंच गया है, जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। बता दें कि उनका यह आकलन बीते 11 फरवरी को ही सच साबित हो गया था। वहीं शनिवार (22 फरवरी) को यह संख्या 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। अभी महाकुंभ के समापन में 05 दिन शेष हैं और महत्वपूर्ण महाशिव रात्रि का स्नान पर्व बचा है। पूरी उम्मीद है कि

स्नानार्थियों की यह संख्या 65 करोड़ के ऊपर जा सकती है।

अब तक के कुल स्नानार्थियों की संख्या का विश्लेषण करें तो सर्वाधिक करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था। जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया। एक फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई। इसके अलावा बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं माघी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर भी दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने महाकुंभ को बताया शांति का संदेश



महाकुंभ नगर, 22 फरवरी
(एजेंसियां)।

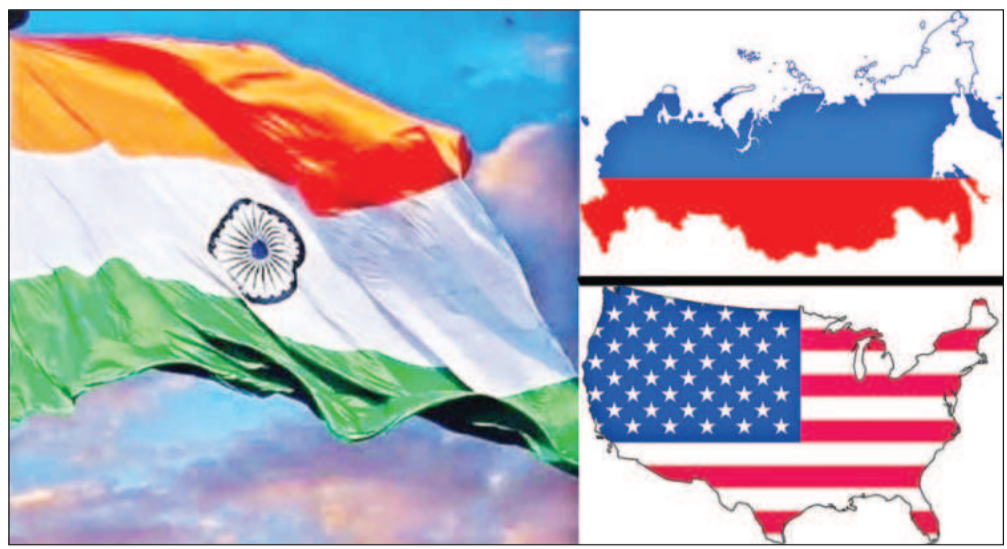
महाकुंभ 2025 में राजनीतिक हस्तियों का आगमन लगातार जारी है। इसी क्रम में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने महाकुंभ में शामिल होकर गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने इसे सभ्यता का प्रतीक और शांति का संदेशवाहक बताया।

अन्नामलाई ने कहा, यह एक अद्वितीय स्थान है, जहां हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से चलती आ रही है।

अब तक 60 करोड़ लोग यहां आ चुके हैं, पूरी तरह शांतिपूर्वक स्नान कर गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन ही

नहीं, बल्कि विश्व शांति का संदेशवाहक बताया। उन्होंने कहा, जब ये 600 मिलियन लोग वापस अपने घर जाएंगे, तो वे शांति और प्रेम का संदेश लेकर जाएंगे। इससे उनके घर, समाज और देश बेहतर बनेंगे और अंततः पूरी मानवता महान बनेगी।

महाकुंभ 2025 में अब तक कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। प्रयागराज में इस भव्य आयोजन के दौरान देश-विदेश के नेता, संत, विद्वान और भक्तगण बड़ी संख्या में उप-स्थित हो रहे हैं। अन्नामलाई ने इस आध्यात्मिक अनुभव को सम्पूर्ण मानवता के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि महाकुंभ का यह संदेश भारत के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर में गुंजेगा।



अमेरिका धोखेबाज है पर रूस भारत का है पक्का दोस्त

मास्को, 22 फरवरी (एजेंसिया)। अमेरिका की भारत से यारी दिखावा है। वजह है टैरिफ। जो हां, एक ओर वह भारत को अच्छा दोस्त बताते हैं, दूसरी ओर वह भारत पर टैरिफ की धमकी देते हैं। ऐसे ही मौकों पर हमें समझ आता है कि हमारा पक्का यार तो रूस ही है। रूस ही हमारा ऐसा पक्का यार है जो हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहता है। भारत भी उसके मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है। चाहे वह अमेरिका का प्रतिबंध का वक्त हो या यूक्रेन संग जंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का अगर कोई पक्का वाला दोस्त है तो

वह है रूस। उधर यूक्रेन जंग पर पुतिन को ट्रंप झंसे में लेने की कोशिश में जुटे हैं। इधर होली से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस से अपनी दोस्ती का रंग और गाढ़ा करने में जुटे हैं। जो हां, गुरुवार को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे खत्म हो, इस पर भी दोनों देशों के विदेशमंत्रियों के बीच बातचीत हुई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के उपाय सुझाए। जयशंकर दो दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका गए हैं। उन्हें जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव संग मुलाकात वाली तस्वीरें एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जोहान्सबर्ग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। दोनों के बीच क्या-क्या बातचीत हुई, इसका विवरण भी दिया। उन दोनों ने भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।

यानी दोनों देश एक-दूसरे के सहयोग से कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इस पर बात हुई। इतना ही नहीं, जयशंकर और लावरोव ने यूक्रेन-जंग से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की, जिसमें रियाद बैठक भी शामिल है। रियाद में पुतिन और ट्रंप के प्रतिनिधि मिले थे और यूक्रेन जंग पर शांति की कवायद पर बातचीत हुई है। मोशाल मीडिया पर कई वीडियो में जयशंकर और लावरोव हाथ मिलाते हुए देखे गए। एक वीडियो में दोनों नेता एक साथ पोज देते और बाद में अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए बैठते दिख रहे हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिकी कोर्ट ने हार्दी मतार को लेखक रुशदी पर हमले का दोषी ठहराया



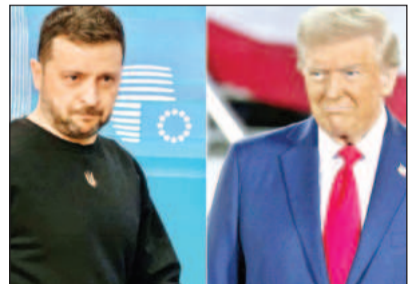
न्यूयॉर्क। पश्चिमी न्यूयॉर्क स्थित चौटाउका काउंटी कोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश लेखक सलमान रुशदी पर तीन साल पहले चाकू से हमला करने के आरोपित 27 वर्षीय हार्दी मतार को दोषी करार दिया। रुशदी पिछले सप्ताह शुरू हुई गवाही प्रक्रिया के दौरान मुख्य गवाह रहे। रुशदी ने जुरी के सदस्यों को अपनी दाहिनी आंख भी दिखाई जिसकी रोशनी हमले के कारण चली गई है। जुरी ने हार्दी मतार को उस व्यक्ति पर भी हमला करने का दोषी पाया जो उस समय रुशदी के साथ मंच पर था। सलमान रुशदी पर हमले का वाक्या 12 अगस्त, 2022 का है। आरोपित ने मंच पर चढ़कर रुशदी पर 15 बार चाकू से वार किया। इस हमले में 77 वर्षीय लेखक के एक आंख की रोशनी चली गई। जज ने सजा के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। मतार को 32 साल तक की जेल हो सकती है। जिला अर्टोनी जेसन रिमट ने शुक्रवार को जिरह के दौरान जुरी को हमले का वीडियो दिखाया। इसमें हमलावर मंच पर चढ़कर रुशदी की ओर दौड़ा दिख रहा है। बुकर पुरस्कार विजेता रुशदी ने जुरी सदस्यों को बताया कि हमलावर उन पर तब तक चाकू से वार करता रहा जब तक कि आरुपास खड़े लोगों ने उसे दबाव नहीं लिया। रिमट ने जुरी सदस्यों को एक ट्रामा सर्जन की गवाही की याद दिलाई, जिसने कहा था कि रुशदी की चोटें त्वरित उपचार के बिना घातक हो सकती थीं।

हमास ने गाजा में छह बंधक रिहा किए समझौते के अगले चरण के लिए रखी शर्त

गाजा पट्टी। आतंकवादी समूह हमास और इजराइल के बीच कतर में पिछले माह हुए संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई समझौते ने आज कई परिवारों के चेहरों में खुशी लौटा दी। हमास के नकाबापोशा सशस्त्र

लड़ाकों ने आज सुबह (स्थानीय समयानुसार) मध्य गाजा के नुसीरात में ओमर शेम टॉव (22), पहिया कोहेन (27) और ओमर वेनकर्ट (23) को रेडक्रॉस के अधिकारियों को सौंप दिया। इसके अलावा हमास की कैद से आजाद हुए टाल शोहम (40) और एवेरा मंगिस्टु (38) इजराइल पहुंच गए। गाजा सिटी में रिहा होने वाले छठा बंधक हिशाम अल-सद्वे (37) है। हमास ने समझौते के अगले चरण में बाकी बंधकों की रिहाई के लिए शर्त रखी है। एवेरा मंगिस्टु और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को हवाई मार्ग से गाजा सीमा के पास एक इजराइली सैन्य अड्डे पर पहुंचाया गया। वहां से सभी को इजराइली वायु सेना के हेलीकॉप्टर से मध्य इजराइल के एक अस्पताल ले जाया गया। मंगिस्टु को जांच के बाद घर भेजा जाएगा। शोहम और मंगिस्टु को सुबह दक्षिणी गाजा के शहर राफाह में रिहा किया गया। इन दोनों को सात अक्टूबर, 2023 को किबुजा बरी से अगवा किया गया था।

जेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से हटाने की योजना बना रहे ट्रंप



कीव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चुनावी वादा था कि वह सत्ता में आने पर रूस और यूक्रेन युद्ध तुरंत प्रभाव से रुकवा दूंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि युद्ध रुकवाने से ज्यादा ट्रंप की मंशा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पद से हटाने की है। वह बीते कुछ दिनों से जेलेंस्की पर हमलावर दिख रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताकर कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रुव रेटिंग तेजी से कम हुई है। उन्हें अब पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद साफ हो गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की को पद से हटाकर किसी नए चेहरे को सत्ता में बैठाया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जेलेंस्की की जगह वे कौन से चेहरे हैं, जिन्हें यूक्रेन की बागडोर सौंपी जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा नाम यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का है। पोरोशेंको को सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जिसके बाद वे अगला चुनाव नहीं जीत सके। दूसरा नाम दिमित्रो कुलेबा का है। उन्हें जेलेंस्की का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति को लेकर जो भी सर्वे हुए हैं, उनमें कुलेबा प्रमुखता से आगे रहे हैं। वे जेलेंस्की की सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। उनका 2023 में पाकिस्तान का दौरा बहुत चर्चा में रहा था जहां यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हथियारों को लेकर डील की बहुत चर्चा हुई थी। इसके अलावा तीसरे दावेदार विताली किम हैं। वे मायकोलेव ऑब्लान्स्ट गर्वनर रह चुके हैं। वह यूक्रेन के बड़े कारोबारी भी हैं।

बड़बोले निकले डोनाल्ड ट्रंप-निर्वासन अभियान में बाइडेन से रह गए पीछे

वॉशिंगटन 22 फरवरी (एजेंसिया)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काम कम बाते ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को इतिहास के सबसे बड़े निर्वासन अभियान के तहत बाहर करेंगे। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद उनका यह ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक रफतार नहीं पकड़ पाया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने 37,660 लोगों को देश से बाहर निकाला, जो कि जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में औसत 57,000 प्रति माह से काफी कम है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में निर्वासन की संख्या में तेजी आएगी, क्योंकि अब गिरफ्तारियों और निष्कासन के नए रास्ते खोले जा रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के प्रवासियों को 'ग्वानामो' के स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर भेजना शुरू कर दिया है। जनवरी के अंत में ट्रंप ने घोषणा की थी कि वहां 30,000 प्रवासियों को रखने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम पर नाराजगी जताई है।

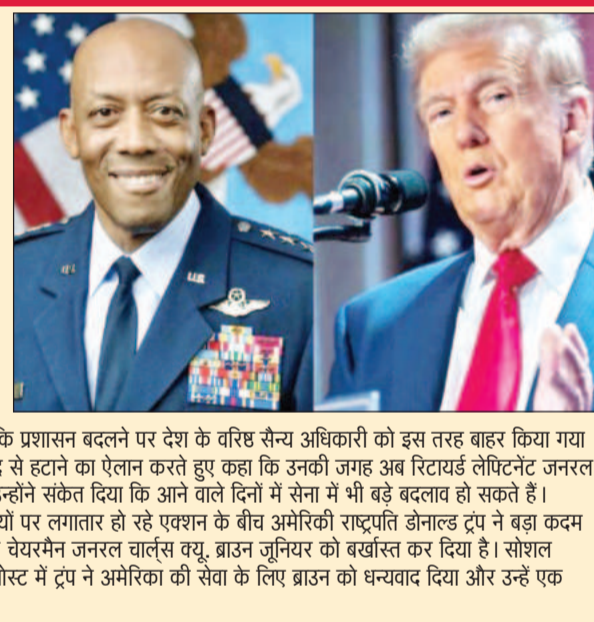
ट्रंप प्रशासन अब उन प्रवासियों को भी निशाने पर ले रहा है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन जिनके खिलाफ अंतिम निर्वासन आदेश जारी हो चुका है। हाल ही में न्याय विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिससे आक्रामक अदालतों के अंदर से ही आईसीडी अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के कुख्यात आपराधिक गिरोह सहित सात अन्य गैंग्स और ड्रग कार्टेल्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस कदम से इनसे जुड़े प्रवासियों को निर्वासित करना और भी आसान हो जाएगा।

ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले तीन हफ्तों में 14,000 से अधिक प्रवासियों को गिरफ्तार किया, जो कि पिछली औसत दर से लगभग दोगुना है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शुरूआती बढ़त के बावजूद इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। आईसीडी के पास इस समय 41,100 प्रवासियों को हिरासत में रखने की क्षमता है, जबकि नए बजट में इसे बढ़ाने पर चर्चा जारी है।



ट्रंप ने सेना के टॉप जनरल को किया बर्खास्त

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कार्यशैली को लेकर पूरी दुनिया में चर्चित हैं। कब कौन सा आदेश निकाल दें कोई नहीं जानता। बीते रोज ट्रंप ने टॉप जनरल को बर्खास्त कर अपने ही अधीनस्थों में खींच पैदा कर दिया है। उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को अपने टॉप मिलिट्री जनरल को बर्खास्त कर दिया। जवाइंट चीफ्स चैयरमैन जनरल चार्ल्स व्यू. ब्राउन जुनियर को नौकरी से निकालकर बर्खास्त कर दिया। यही पहली बार हुआ है कि प्रशासन बदलने पर देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को इस तरह बाहर किया गया है। ट्रंप ने सी.व्यू. ब्राउन को पद से हटाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जगह अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में सेना में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों पर लगातार हो रहे एक्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जवाइंट चीफ्स चैयरमैन जनरल चार्ल्स व्यू. ब्राउन जुनियर को बर्खास्त कर दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू पर लिखा पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिका की सेवा के लिए ब्राउन को धन्यवाद दिया और उन्हें एक अच्छा सज्जन बताया।



डब्ल्यूएचओ ने शराब को माना विषैला और लत पैदा करने वाला पदार्थ



हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शराब को एक विषैला और लत पैदा करने वाला पदार्थ माना है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने कैंसर उत्पन्न करने वाले सबसे खतरनाक पदार्थों में वर्गीकृत किया है। डब्ल्यूएचओ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन को लेकर चेतावनी जारी की है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और यह 20 से अधिक प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सेवन मुंह, गला, भोजन नली, पेट, बृहदान्त्र, मलाशय और अग्न्याशय के कैंसर से जुड़ा हुआ है। महिलाओं में यह स्तन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का भी कारण बन सकता है। अल्कोहल का सेवन शरीर में एक जहरीले यौगिक, एसिटल्डिहाइड को उत्पन्न करता है, जो डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी होंगे मॉरीशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह के सम्मानित अतिथि

मॉरीशस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री रामगुलाम ने की घोषणा, सदस्यों ने मेज थपथपाकर जताई खुशी

पोर्ट लुइस, 22 फरवरी (एजेंसिया)।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने नेशनल असेंबली में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वो मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सम्मानित अतिथि होंगे। यह हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है। रामगुलाम की इस घोषणा पर नेशनल असेंबली के सदस्यों ने मेज थपथपाकर खुशी जताई।

रामगुलाम ने शुक्रवार को कहा, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी करना हमारे और देश के



लिए वास्तव में गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम, पेरिस और संयुक्त

राज्य अमेरिका की अपनी हालिया यात्राओं के बावजूद हमें यह सम्मान दिया है। वह हमारे विशेष

काश पटेल ने हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर हाथ रखकर ली एफबीआई निदेशक पद की शपथ



वॉशिंगटन, 22 फरवरी (एजेंसिया)। संघीय जांच ब्यूरो के नवनियुक्त निदेशक काश पटेल शुक्रवार को आधिकारिक रूप से शपथ लेने के बाद सुर्खियों में हैं। हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर शपथ लेने का उनका फैसला अयोध्या के राम मंदिर पर पश्चिमी मीडिया कवरेज की उनकी पिछली आलोचना से मिलता जुलता है। काश पटेल ने एफबीआई के नौवें निदेशक के रूप में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। पटेल (44) के पक्ष में बृहस्पतिवार को रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सीनेट में 49 के मुकाबले 51 मत पड़े। वह देश की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय-

अमेरिकी बन गए हैं। शुक्रवार को शपथ समारोह के दौरान पटेल के परिवार के सदस्य और उनकी महिला मित्र मौजूद थीं। शपथ समारोह का संचालन अमेरिकी अर्सेनील जनरल पाम बॉडी ने व्हाइट हाउस परिसर में "आइजनाहवर कार्यकारी कार्यालय भवन (ईईओबी) में भारतीय संधि कक्ष में किया। उन्होंने पटेल से गीता पर हाथ रखने और शपथ लेने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाने को कहा। पटेल ने कहा, "मैं अमेरिकी सपना जी रहा हूँ। जो कोई भी सोचता है कि अमेरिकी सपना मर चुका है, वह यहां देख ले। आप पहली पीढ़ी के भारतीय बच्चे से बात कर रहे हैं, जो ईश्वर की हरी-भरी धरती पर सबसे महान राष्ट्र, कानून प्रवर्तन समुदाय का नेतृत्व करने वाला है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता।" न्यूयॉर्क में जन्मे पटेल गुजरात से संबंध रखते हैं। हालांकि उनके माता-पिता पूर्वी अफ्रीका से हैं। उनकी मां तंकाजिया से और उनके पिता युगांडा से हैं। वे 1970 में कनाडा से अमेरिका आए थे। पटेल के माता-पिता अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपना समय अमेरिका तथा गुजरात दोनों में बिताते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए उनसे बातचीत भी की थी।

मेरे दोस्त, जीत की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जीत के बाद मेरी मेरे दोस्त जीत रामगुलाम से बात हुई। मैंने उन्हें ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। हम अपनी विशेष साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

गारत और मॉरीशस के संबंध

भारत और मॉरीशस के बीच इतिहास और संस्कृति आधारित गहरा रिश्ता है। मॉरीशस में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉरीशस में 8 लाख 94 हजार 848 भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी है।

जेल जाते वक्त जब संजय दत्त को प्रेग्नेंट बीवी मान्यता की हुई चिंता

अभिनेत्री शीबा आकाशदीप को किया था फोन, 9 महीने तक रही साथ



बॉ लीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल होने के लिए पांच साल की जेल की सजा काटी थी। उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था और 2016 में रिहा होने से पहले उन्हें अपनी सजा के दौरान कई बार जमानत दी गई थी। 2009-2010 के आसपास जेल में रहने के दौरान, संजय की पत्नी मान्यता दत्त अपने जुड़वां बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थीं। आगे जेल की सजा का सामना करने पर, संजय ने अपनी करीबी दोस्त और साथी अभिनेत्री शीबा आकाशदीप से संपर्क किया और उनसे उनकी अनुपस्थिति में मान्यता का साथ देने के लिए कहा।

कितना मुश्किल था वो समय : शीबा

हाल ही में पिकविला से बातचीत में, शीबा ने संजय के जीवन के इस कठिन दौर को करीब से देखने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह मान्यता के साथ उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान खड़ी रहीं और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन नौ महीनों के दौरान वह अकेली न रहें। शीबा ने कहा, जब वह जेल जा रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'मान्यता अकेली है, मैं

चाहता हूँ कि तुम जाकर उसकी देखभाल करो'। मैं रोजाना अपने घर से उसके पास बैठने जाती थी ताकि मैं उसके साथ रह सकूँ क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और अकेली थी। मैं उसके बाहर आने तक उसके साथ रहना चाहता थी। इसलिए, मैंने पूरे नौ महीने उसके साथ बिताए।

जेल में ये काम करते थे संजय

इससे पहले, शेफ रणवीर बार के होस्ट शो स्टार बनाम फूड सर्वाइवल में पहुंचे संजय दत्त ने खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने जेल में अपने समय का इस्तेमाल एक्सरसाइज करने और खाना बनाना सीखने के लिए किया। संजय ने कहा, पहली बार जब मैं जेल गया था, अगर आप ठाणे जेल के बाहर की तस्वीरें देखें- अन्न, अक्षय, अजय, शाहरुख, हर कोई मेरे पास आया और मुझे शुभकामनाएं दीं। मुझे जेल की सजा काटने से कोई राहत नहीं मिली, इसलिए इस बारे में ज्यादा क्यों सोचना? मुझे अपना मन बनाना पड़ा कि हां मुझे जाना ही है। मुझे इसका सामना करना होगा। छह सालों में, मैंने इसका सामना किया, इसे संभाला, इसका पूरा फायदा उठाया और इससे सीखा। मैंने उस समय का इस्तेमाल खाना बनाना, शास्त्र सीखना और



वर्कआउट करने में किया। मैं एक बेहतर काया के साथ बाहर आया।

साउथ ला रहा है दृश्यम 3

सुपरस्टार मोहनलाल बोले- अतीत कभी चुप नहीं रहता

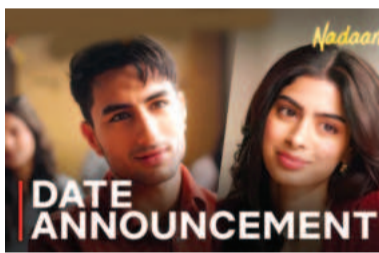


म लयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे सीकल की घोषणा कर दी है। इस फिल्म के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं। दोनों की पार्ट को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इतना ही नहीं दृश्यम 1 और दृश्यम 2 को कई भाषाओं में रीमेक कर रिलीज किया गया है। अब 20 फरवरी को मोहनलाल ने दृश्यम 3 की घोषणा कर डाली है। उनकी इस फिल्म का निर्देशन भी जीतू जोसेफ करने वाले हैं। अपनी इस फिल्म की घोषणा मोहनलाल ने सोशल मीडिया के जरिए की है।

फिल्म नादानियां 7 मार्च को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

ब्राह्मि अली खान और खुशी कपूर स्टार फिल्म नादानियां के निर्माताओं ने रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। फिल्म 7 मार्च को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। नादानियां ब्राह्मि अली खान की पहली फिल्म है। वहीं, खुशी कपूर की यह द आर्चीव, लवयापा के बाद तीसरी फिल्म है।

नेटफ्लिक्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने इसकी घोषणा की और लिखा, कुछ कुछ होता है ऐसी नादानियां देखकर, 7 मार्च को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर नादानियां रिलीज हो रही है। नादानियां में ब्राह्मि अली के किरदार का नाम अर्जुन मेहता है। वहीं, खुशी कपूर के किरदार का नाम पिया जय सिंह है। नादानियां जेन जेड के रोमांस, प्यार और उसमें आने वाले मुश्किलों को पर्दे पर उतारती है। निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म नादानियां के दूसरे ट्रेक गलतफहमी को रिलीज किया है। फिल्म का गाना प्यार के बीच आने वाली मुश्किलों को दिखाता है। इंस्टाग्राम हैंडल पर गाना शेयर करते हुए निर्माताओं ने लिखा, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्यार किया, खोया



और कभी समझा नहीं पाए! गलतफहमी गाना रिलीज हो चुका है। गलतफहमी गाने को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने गाने के बोल लिखे हैं। ट्रेक को आवाज तुषार जोशी और मधुबंती बागची ने दी है। इब्राहिम ने कहा, गलतफहमी में कुछ ऐसा है जिससे आप जुड़ सकेंगे। यह वास्तविक है और दिल टूटने के दर्द को दिखाता है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि दर्शक इससे कैसे जुड़ते हैं। यह प्यार और नुकसान का एक ऐसा पहलू है जो भरोसेमंद है। खुशी ने कहा, गलतफहमी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया और यह नादानियां एल्बम के

मेरे पसंदीदा ट्रेक में से एक है। मुझे विश्वास है कि दर्शक गलतफहमी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। मैं लोगों के बीच इसे पेश करके काफी खुश हूँ। शौना गौतम के निर्देशन में बनी नादानियां को धर्मा एंटरटेनमेंट के तहत करण जोहर, अपूर्व मेहता और सोमेश मिश्रा ने तैयार किया है। यह फिल्म प्यार के कॉन्सेप्ट को एक नए मोड़ के साथ पेश करती है।

जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट का पहला गाना भारत जारी, मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं बोल

जॉ न अब्राहम पिछली बार फिल्म वेदा में नजर आए थे, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। काफ़ी समय से जॉन अपनी आगामी फिल्म द डिप्लोमैट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान शिवम नायर ने संभाली है। यह फिल्म 7 मार्च, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अब इससे पहले निर्माताओं ने द डिप्लोमैट का पहला गाना भारत जारी कर दिया है। भारत गाने को हरिहरन ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है। फिल्म में सादिया खतीब, रेवती, कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी जैसे कलाकार भी हैं। द डिप्लोमैट एक भारतीय राजनयिक के पाकिस्तान से भारतीय लड़की को वापस लाने के प्रयासों की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में जॉन



इस्लामाबाद में भारत के पूर्व उप उच्चायुक्त जेपी सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में बात करते हुए जॉन ने कहा, कूटनीति एक युद्ध का मैदान है, जहां शब्दों का वजन हथियारों से ज्यादा होता है। जेपी सिंह की भूमिका निभाने से मुझे एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका मिला जहां शक्ति को बुद्धि, लचीलापन और शांत वीरता से परिभाषित किया जाता है। उजमा की कहानी भारत की ताकत और साहस का प्रमाण है और मुझे इस प्रेरक यात्रा को स्क्रीन पर जीवंत करने पर गर्व है।

शमा सिकंदर ने हॉटनेस से सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा

टी वी एक्ट्रेस शमा सिकंदर आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों फैंस के बीच शेयर करती रहती हैं। उनका बॉल्ड और कातिलाना अंदाज इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों फैंस के बीच साझा की हैं। इन तस्वीरों में उनका किलर और हॉट लुक देखकर फैंस एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। एक्ट्रेस शमा सिकंदर हमेशा अपने लुक से इंटरनेट पर कहर बरपाती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों साझा की हैं। इन तस्वीरों में उनका कातिलाना अवतार देखकर फैंस एक बार फिर से अपने होश खो बैठे हैं। बता दें कि एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरों इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। शमा सिकंदर की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने व्हाइट कलर का फर् लुक में स्वेटर पहना हुआ है, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टनिंग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने अपने इस आउटलुक को कंप्लीट करने के लिए कानों में इयररिंग्स, खुले बाल और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है। शमा सिकंदर की इन फोटोज पर एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा है- टू मट हॉट। दूसरे यूजर ने लिखा है- बॉल्ड एंड ब्यूटिफुल। तीसरे यूजर ने लिखा है- हॉट एंड सेक्सी। बता दें कि शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट भी काफी जबरदस्त है। उनका हर एक अंदाज इंस्टाग्राम पर आते ही बवाल मचाने लगता है।



अनुपम खेर की नई फिल्म तुमको मेरी कसम का ऐलान

वि क्रम भट्ट बॉलीवुड में अपनी हॉरर जॉनर की फिल्मों के लिए फेमस है। जल्द ही रिलीज होने वाली उनकी फिल्म तुमको मेरी कसम रिलीज होगी। इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें फिल्म की कहानी में थ्रिलर का तड़का है, साथ ही कोर्ट रूम ड्रामा भी नजर आ रहा है। फिल्म तुमको मेरी कसम में अनुपम खेर एक आईवीएफ हॉस्पिटल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म के टीजर में कोर्ट रूम सीन भी दिख रहे हैं। क्या है आईवीएफ और कोर्ट केस का नाता, यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन टीजर में अनुपम खेर, अदा शर्मा और ईशा देओल के डायलॉग दमदार लग रहे हैं। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम मार्च के महीने में रिलीज होगी। यह फिल्म 21 मार्च को



सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्रम भट्ट इस फिल्म को इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी ने प्रोड्यूस किया है। महेश भट्ट भी इंदिरा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। फिल्म की प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्वेतांबरी भट्ट, कृष्णा भट्ट सरदा हैं। फिल्म तुमको मेरी कसम में अनुपम खेर, अदा शर्मा के अलावा इशाक सिंह, ईशा देओल, मेहरजान मज्दा और सुशांत सिंह भी नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर के किरदार के आगे फिल्म की कहानी को बुना गया है। यह फिल्म डॉ. अजय मुर्दिया की जिदगी से इंस्पायर बताई जा रही है। विक्रम भट्ट ने इस कहानी को निर्देशित करने के साथ लिखा भी है। फिल्म तुमको मेरी कसम के जरिए एक इमोशनल, थ्रिलर स्टोरी को विक्रम भट्ट दिखा रहे हैं लेकिन वह हॉरर फिल्मों के मास्टर माने जाते हैं।

पराशक्ति से विजय एंटनी की पहली झलक आई सामने, हिंदी समेत चार भाषाओं में होगी रिलीज

द क्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता-संगीतकार और निर्माता विजय एंटनी काफ़ी समय से अपने करियर की 25वीं फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशक की कमान निर्देशक अरुण प्रभु ने संभाली है। यह फिल्म इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है, जिसका प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब निर्माताओं ने इस फिल्म के शीर्षक से पर्दा उठ गया है। इसके साथ फिल्म से विजय की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। विजय की आगामी फिल्म का नाम पराशक्ति रखा गया है। सामने आए पोस्टर में अभिनेता का धांसू अवतार दिख रहा है। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जो हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। इस फिल्म में वागई चंद्रशेखर, सुनील कृपलानी, सेल मुग्गन, तृप्ति रवींद्र और बाल कलाकार मास्टर केशव जैसे सितारे भी नजर आएंगे। विजय एंटनी की पिछली फिल्म मझाई पिडिकथा मनिथन दर्शकों को प्रभावित करने में विफल रही, लेकिन विशाल अभिनीत माधा गज राजा के लिए उनके संगीत को प्रशंसकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।



विजय एंटनी गगन मार्गन का भी हिस्सा हैं, जो निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है। पराशक्ति और अन्य आगामी परियोजनाओं के साथ विजय एंटनी की पैक लाइनअप उनके प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक वर्ष का वादा करती है। जैसा कि विजय एंटनी इस गर्मी में पराशक्ति की रिलीज के लिए तैयार हैं, प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अभिनेता उनके लिए क्या लेकर आए हैं। अपने संगीत और अभिनय कौशल के साथ विजय एंटनी फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और उनकी 25वीं फिल्म एक खास होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि विजय इस फिल्म के निर्माता हैं। इतना ही नहीं, वह फिल्म के संगीतकार भी हैं।

